जनसत्ता

लापरवाही की लपटें

दिल्ली की अनाजमंडी में लगी आग से दम घुटने और झुलस कर तिरालीस लोगों की मौत ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही और असंवेदनशीलता को रेखांकित किया है। उपहार सिनेमा कांड के बाद आग लगने की यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है, जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई। इसी साल करोलबाग के एक होटल में लगी आग से करीब चौदह लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा ऐसे छिटपुट हादसे होते रहते हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अनाजमंडी की जिस इमारत में आग लगी, वहां अवैध रूप से कारखाना चल रहा था, जिसमें प्लास्टिक और कागज से चीजें बनाई जा रही थीं। इसी के एक हिस्से में वहां काम करने वाले मजदूर रहते थे। रविवार की सुबह जब आग लगी, तो वे वहां सो रहे थे। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, इसलिए ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाए और झुलस गए। इसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। आग लगने की वजह बिजली के तारों का गरम होकर जल उठना बताया जा रहा है। हालांकि बिजली के मीटर सही अवस्था में पाए गए हैं, इसलिए इसकी वजह कोई दूसरी भी हो सकती है। अभी इसकी छानबीन चल रही है।

आग लगने की अब तक जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वह अवैध रूप से चलाए जा रहे कारखानों में हो या फिर किसी होटल, बाजार आदि में, सबमें यही देखा गया है कि वहां सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई थी। फिर सवाल है कि ऐसी जगहों पर निगरानी रखने वाला तंत्र तब तक क्यों आंखें बंद किए रखता है, जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। छिपी बात नहीं है कि इस तरह छोटे पैमाने पर चलाए जाने वाले कारखानों में अक्सर आग लगने, भूकंप आदि की स्थितियों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप निकास, अग्निशमन यंत्र, बिजली के तारों आदि पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी बड़ी वजह है कि संबंधित महकमे इन लापरवाहियों की अनदेखी करते हैं या फिर किसी सांठगांठ या प्रभाव के चलते उनके खिलाफ कड़ाई नहीं करते। विचित्र है कि ऐसे बहुत सारे कारखाने सघन बसे रिहाइशी इलाकों में चलते हैं, जहां एक इमारत की आग बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है, पर वहां भी प्रशासन को लापरवाह ही देखा जाता है। अनाजमंडी के कारखाने में मारे गए लोग भी मालिकों और प्रशासन की इसी लापरवाही की भेंट चढ़ गए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अदालतें अनेक मौकों पर फटकार लगा और सख्त निर्देश दे चुकी हैं कि रिहाइशी इलाकों में चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाए। मगर फौरी सक्रियता के बाद हर बार लंबी शिथिलता पसर जाती है। फिर दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जो अनधिकृत कॉलोनी के रूप में बसे थे और सरकार ने उन्हें अधिकृत घोषित कर दिया। इससे वहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर की व्यवस्था तो हो गई, पर उनकी बसावट इस कदर सघन है कि वहां दमकल की गाड़ियों आदि के पहुंचने में भी कठिनाई आती है। वहां बड़े पैमाने पर ऐसे कारखाने चल रहे हैं, जिन्हें यह मान कर चलने दिया जाता है कि वे प्रदूषण नहीं फैलाते। इसी तरह दिल्ली के गांवों में बड़े पैमाने पर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। दोनों सरकारों को ऐसे कारखानों को लेकर कोई व्यावहारिक नीति बनाने की जरूरत है, ताकि मौत की वजह बनने वाले हादसे दुहराए न जा सकें।

बेलगाम अपराध

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार की जिस पीड़िता को पिछले हफ्ते जिंदा जला दिया गया था, आखिरकार उसकी मौत हो गई। यह घटना हैदराबाद में एक पशु-चिकित्सक युवती के साथ ठीक इसी तरह की घटना यानी उसके बलात्कार के बाद जिंदा जला दिए जाने के कुछ ही दिन बाद हुई। विडंबना है कि उन्नाव की घटना के आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में उसे जमानत पर जेल से छोड़ दिया गया था। जबकि आमतौर पर माना जाता है कि बलात्कार के मामलों में आरोपी को जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। आरोपों के मुताबिक गुरुवार को सामने आई इस घटना में जमानत पर बाहर आए मुख्य आरोपियों के अलावा चार अन्य लोगों ने पीड़ित लड़की को रास्ते में एक सुनसान जगह पर घेर कर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। जब वे भाग गए, तब लड़की किसी तरह एक घर तक पहुंची और वहां उसे मदद मिल सकी। इस मामले में जितने ब्योरे अब तक सामने आ सके हैं, उसके मुताबिक यह त्रासद घटना बहुस्तरीय लापरवाही का नतीजा है कि एक लड़की के खिलाफ पहले बलात्कार जैसा अपराध हुआ और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। इस बीच परिवार ने कई बार आरोपियों की ओर से भयावह अंजाम भुगतने की धमकी की बात कही, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्रशासन को समय पर कोई उचित कदम उठाना जरूरी क्यों नहीं लगा!

दरअसल, कानूनी प्रक्रिया में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उसे अगर सुविधा के मुताबिक देखा जाता है तब इंसाफ मिलने में देरी या बाधा स्वाभाविक है। उन्नाव मामले में अगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लिया होता, उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाती, तो शायद वह जिंदा होती। लेकिन समय पर जरूरी कदम नहीं उठाने का ही नतीजा है कि जमानत पर छूटे आरोपी ने सबूत मिटाने के मकसद से पीड़िता को जलाने की कोशिश की। गनीमत है कि मरने से पहले पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए और उनकी गिरफ्तारी हो सकी। लेकिन इससे पुलिस इस बात की जवाबदेही से नहीं बच सकती कि आरोपी के जमानत पर छूटने के बाद पीड़िता पर खतरे थे, तो उस संदर्भ में उसने क्या किया! कुछ खबरों में बताया गया कि पीड़िता और आरोपी में पहले से दोस्ती थी। सवाल है कि अगर ऐसा था तो भी किसी को महिला के खिलाफ अपराध करने की छूट कैसे मिल जाती है? यह तर्क न केवल कानून, बल्कि एक सभ्य और मानवीय समाज के सभी मूल्यों के खिलाफ है।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि हैदराबाद में बलात्कार और बर्बर हत्या के मामले और उसके बाद समूचे देश में उपजे आक्रोश के बावजूद न तो दूसरे राज्यों की सरकारों और पुलिस के रवैये में कोई फर्क आया और न बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों को डर लगा। अफसोसनाक है कि हैदराबाद की घटना के बाद देश के अलग-अलग इलाकों से कम से कम चार ऐसी ही घटनाएं सामने आईं, जिनमें बलात्कार के बाद महिला को जिंदा जला दिया गया। आखिर क्या वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में पसरे अपराधी मानस वाले लोगों के भीतर सजा का खौफ नहीं रह गया है? हैदराबाद में पुलिस ने कथित मुठभेड़ में आरोपियों को मार गिराया। लेकिन जब तक समयबद्ध कार्रवाई के तहत सही आरोपियों को कठघरे में खड़ा करने और उसके लिए सजा तय करने की व्यवस्था नहीं होती, तब तक न्याय सुनिश्चित करना मुश्किल बना रहेगा।

कल्पमेधा

पत्तों पर नृत्य करती हुई ओस की तरह
अपने जीवन को समय के पत्तों
पर नृत्य करने दो।
– रवींद्रनाथ ठाकुर

रोजगार योग्य शिक्षण-प्रशिक्षण जरूरी

जयंतीलाल भंडारी

इस समय देश में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी के मद्देनजर जीवन गुणवत्ता, सार्वजनिक शिक्षा पर अधिक व्यय और कौशल विकास से ही रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं। चूंकि ऐसी स्थिति अभी नहीं है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने श्रमबल के नवीनतम आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि सन 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसद रही है। देश में बेरोजगारी की यह दर पैंतालीस साल में सर्वाधिक है।

इन दिनों रोजगार संबंधी विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों में यह तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि 2030 तक युवाओं के लिए जो रोजगार की चमकीली संभावनाएं उभर रही हैं, उनको साकार करने के लिए भारत में रोजगार के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण को नई पीढ़ी का मूलमंत्र बनाया गया तो भारत तेजी से विकास करेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में रोजगार की समस्या बड़ी मुश्किल का कारण बन जाएगी।

गौरतलब है कि इस समय देश और दुनिया में भारत से संबंधित शैक्षणिक और प्रशिक्षण की विश्व रैंकिंग से संबंधित दो रिपोर्ट को गंभीरता से देखा जा रहा है। बीते 26 नवंबर को प्रकाशित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग-2020 में कहा गया है कि 2019 में भारत के अधिकतर प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में गिरावट आई है। देश का कोई भी शिक्षण संस्थान अन्य एशियाई संस्थाओं की तुलना में शीर्ष तीस में जगह नहीं बना सका। आइआइटी मुंबई पिछले वर्ष के मुकाबले एक स्थान फिसल कर चौंतीसवें स्थान पर आ गया। आइआइटी दिल्ली तैंतालीसवें और आइआइटी मद्रास अड़तालीसवें स्थान पर है।

इसके मुताबिक 2030 तक शिक्षा अध्ययन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी विद्यार्थियों की आबादी भारत में होगी। ऐसी नई आबादी को रोजगार योग्य बनाने के लिए भारत को अध्ययन तथा शोध कार्य में निवेश बढ़ाना होगा। इसी तरह भारतीय युवाओं की प्रतिभा, गुणवत्तापूर्ण जीवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित पिछले दिनों 18 नवंबर को स्विट्जरलैंड के विश्वविख्यात आइएमडी बिजनेस स्कूल के द्वारा प्रकाशित की गई ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2019 रिपोर्ट के मुताबिक भारत तिरसठ देशों की सूची में पिछले वर्ष के तिरपनवें स्थान से छह पायदान फिसल कर उनसठवें स्थान पर आ गया है।

निस्संदेह प्रतिभा रैंकिंग की इस वैश्विक सूची में प्रतिभाओं के विकास, उन्हें आकर्षित करने और देश में ही जोड़े रखने, उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए किए जा रहे निवेश के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस सूची के प्रकाशन के साथ सूची में शामिल विभिन्न देशों में प्रतिभा की स्थिति के बारे में भी टिप्पणियां की गई हैं। भारत के बारे में कहा गया है कि टैलेंट पूल की गुणवत्ता के मामले में भारत का प्रदर्शन औसत से बेहतर है। लेकिन अपनी शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता और सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की कमी, युवाओं के गुणवत्तापूर्ण जीवन की कमी, प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता में कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी और श्रमबल में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी में कमी के कारण निवेश और विकास के मामले में भारत सूची में शामिल देशों में बहुत पीछे है।

इन रिपोर्टों पर चिंतित होना और आगे बढ़ने की राह निकालना इसलिए जरूरी है, क्योंकि देश की नई पीढ़ी में प्रतिभा को सक्षम बना कर ही रोजगार की उजली संभावनाओं को साकार किया जा सकेगा और देश की तस्वीर को चमकीला बनाया जा सकेगा। भारत की जनसंख्या में करीब पचास प्रतिशत से ज्यादा की उम्र पच्चीस साल से कम और पैंसठ प्रतिशत आबादी की पैंतीस साल से कम है। चूंकि भारत के पास विकसित देशों की तरह रोजगार बढ़ाने के विभिन्न संसाधन और आर्थिक शक्तियां नहीं हैं, इसलिए भारत की युवा आबादी ही जीवन गुणवत्ता के साथ कौशल प्रशिक्षित होकर मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लिए उपयोगी और भारत के लिए आर्थिक कमाई का प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है।

जाहिर है, इस समय देश में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी के मद्देनजर जीवन गुणवत्ता, सार्वजनिक शिक्षा पर अधिक व्यय और कौशल विकास से ही रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं। चूंकि ऐसी स्थिति अभी नहीं है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने श्रमबल के नवीनतम आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि सन 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसद रही है। देश में बेरोजगारी की यह दर पैंतालीस साल में सर्वाधिक है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम का आधिक्य है, लेकिन कौशल की कमी है। उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से सजे-धजे भारतीय युवाओं के लिए देश-विदेश में नौकरियों की कमी नहीं है। लेकिन नौकरियों की योग्यता के अभाव में इस समय ऊंची-ऊंची डिग्री रखने वाले युवा भी नौकरियों से दूर हैं।

इसी तरह पिछले महीने के आखिर में पेश 'केयर रेटिंग्स' के अध्ययन के अनुसार, देश में रोजगार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस अध्ययन में देश में विभिन्न उद्योग-कारोबार और सेवा क्षेत्र से संबद्ध 1,938 कंपनियों को शामिल किया गया था। अध्ययन से पता चला कि रोजगार में वृद्धि 2015-16 में 2.5 प्रतिशत थी। 2016-17 में 4.1 प्रतिशत, 2017-18 में 3.9 प्रतिशत और 2018-19 में 2.8 प्रतिशत रही। इस अध्ययन के मुताबिक, देश में रोजगार वृद्धि पिछले दो वर्षों में धीमी हो गई है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र भी इस समस्या से दो-चार हैं। अठारह से तीस वर्ष के युवाओं की मनरेगा के तहत रोजगार पाने की कतार बढ़ती जा रही है। 2017-18 में करीब अट्ठावन लाख लोग मनरेगा के तहत रोजगार के लिए आए। 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 70.7 लाख हो गई है।

यह समझना जरूरी है कि इस समय दुनिया के साथ-साथ देश का भी रोजगार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ऐसे में रोजगार की जरूरतें भी बदल रही हैं। इस समय उद्योग-कारोबार में रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमता और थ्री-डी प्रिंटिंग सहित नई-नई तकनीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। देश और दुनिया में भारत के कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। लेकिन ख्याति प्राप्त स्टाफिंग फर्म मैनपॉवर ग्रुप के अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उद्योग-कारोबार के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल पेशेवर लोग नहीं मिल रहे हैं।

ऐसे में जरूरी है कि भारत डिग्री के साथ तकनीकी दक्षता और पेशेवर क्षमता से लैस प्रतिभाओं का निर्माण करे। देश में रोजगार के लिए कौशल से लैस प्रतिभाओं का निर्माण इसलिए भी जरूरी है कि रोजगार के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहे रोबोट चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, रोबोट ने मनुष्य को शारीरिक क्षमताओं के मामले में पीछे छोड़ दिया है और अब दिमागी कामों के मामले में भी खासी दखल हो रही है। ऐसे में रोबोट से भी रोजगार प्रतिस्पर्धा के लिए युवाओं के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता जरूरी है।

यह विडंबना ही है कि प्रतिभाओं के विकास में हम आज भी बहुत पीछे हैं। सरकार के द्वारा देश में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय गठित करके कौशल विकास के काम को गतिशील बनाने की पहल के भी आशाजनक परिणाम नहीं आए हैं। निस्संदेह देश में भारतीय शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता से संबंधित अध्ययन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अब कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी और सार्वजनिक शिक्षा पर आबंटन बढ़ाना होगा। एक ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था को अधिक दक्ष और योग्य श्रम बल की जरूरत है, तब शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद हिस्सा खर्च किया जाना जरूरी है, जो इस समय करीब 3.8 फीसदी ही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विभिन्न रिपोर्टों के मद्देनजर मंथन करके नई पीढ़ी को देश और दुनिया की रोजगार जरूरतों के मुताबिक जीवन गुणवत्ता, अच्छे और कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करके प्रतिभाशाली बनाने की डगर पर सरकार कदम आगे बढ़ाएगी, ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, युवाओं के चेहरे पर मुस्कराहट आए और देश आर्थिक विकास की डगर पर आगे बढ़े।

सिनेमाघर की संस्कृति

सुनील मिश्र

पिछले कुछ समय से लगातार यह प्रश्न कौंध रहा है जो सांस्कृतिक अस्मिता की दृष्टि से बहुत मायने रखता है। जिस तरह धीरे-धीरे दर्शक का मन सिनेमाघर से उचट रहा है और उसे विकल्प के रूप में 'नेटफ्लिक्स' से लेकर छोटी अवधि की रोचक फिल्मों को देखने का अवसर यूट्यूब आदि के माध्यम से घर बैठे सुलभ होने लगा है, वह सब देख कर लगता है कि फिल्म निमार्ताओं ने सिनेमा के प्रति उदासीन होते दर्शक की नब्ज टटोल ली है। पिछले एक दशक में सिनेमा जिस तरह की प्रयोगधर्मिता से गुजर रहा है या उसमें वह धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी से फिसलती रेत का अनुभव कर पा रहा है। जो अकेला दर्शक है या दर्शकों का समूह है, वह अपने आकर्षण को अब पृथक करने चला है।

जीवन की आपाधापी, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं और उससे प्रभावित जीवन, बाजार, सुरक्षा, अपराध और महंगाई जैसे बड़े चिंतनीय विषयों के आगे मनोरंजन का माध्यम सिनेमा अब उतना प्रभाव नहीं रख पा रहा, जिसकी अपेक्षा की जाती थी। जिसकी उत्कृष्टता या श्रेष्ठता का अपना पैमाना होता था, वह सिनेमा हमारे दर्शक को थोड़ी ही देर के लिए सही, यथार्थ से मुक्त करता था, हंसाता या रुलाता था, क्रोध दिलाता था, व्यथित करता था, रोमांटिक होने देता था और फिर हौले से उसे उसकी दुनिया में लौट जाने देता था। इतिहास का सिनेमा या सिनेमा का इतिहास इसी तरह का रहा है। इस पूरी धारा को पिछली सदी के अवसान तक हमारे फिल्मकारों ने बखूबी चलाए रखा। इसमें समझदार और प्रबुद्ध निर्माता-निर्देशकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हमारी स्मृति से यह बात चली नहीं गई है कि सामाजिक और पारिवारिक फिल्में, हास्य, मारधाड़ की एक्शन फिल्में, अधिक हिंसा और प्रतिवाद या प्रतिशोध वाली फिल्मों के निर्देशकों के बाकायदा नाम दर्शकों ने रट रखे थे। इसकी प्रकार वह कलाकार अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में भी ठीक-ठीक पहचान बता पाता था। उस पूरे बड़े स्वर्णयुगीन कालखण्ड में चरित्र अभिनेताओं, सहायक अभिनेताओं और यहां तक कि एक-दो दृश्य के लिए भी परदे पर आकर चले जाने वाले कलाकार अपने हस्ताक्षर करके चले जाते थे। बीती सदी के अंतिम दशक में ये सब चेहरे धूमिल होना शुरू हो गए थे। सिनेमा दो धाराओं में बंट चला था। यथार्थवादी सिनेमा के फिल्मकारों ने बाजारू सिनेमा और उसके बनाने वालों को थोड़ा चौकन्ना जरूर किया, लेकिन ऐसे फिल्मकारों का भी रचनात्मक आंदोलन पंद्रह-बीस वर्षों में सिमट कर रह गया। महानायकवाद ने सिनेमा संस्कृति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जिसने समांतर कलाकारों के भविष्य पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया। बाद का हीरो परदे पर खुद ही सब कुछ हो गया।

नई सदी में तो आगे निकलने, दूसरे से अपने को बेहतर दिखाने की स्पर्धा ऐसी हुई कि वह अहंकार, संकीर्णता और कुंठा की अनेक कहानियों के साथ हिंदी सिनेमा संस्कृति की पोल खोलती रही। अब तो स्पर्धी सितारों के बीच सौहार्द की जो पींगे दिखाई देने लगी हैं, वे कितनी सच्ची हैं, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन है, क्योंकि चकाचौंध भरे इस माध्यम से लोकलाज को देखते हुए गले मिलने, एक-दूसरे को सराहने और मुस्कराने का भी अगर समझौता कर लिया जाता हो तो इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के सिनेमा का अर्थ पांच-छह प्रौढ़ नायकों के केंद्र में रहने वाले सिनेमा से लगाया जा सकता है।

दुनिया मेरे आगे

यह भी हो रहा है कि दर्शक इनके सिनेमा को कई बार अस्वीकार कर रहा है। बाजार के आंकड़े और टिकट खिड़की पर धन संग्रह को बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित करने का गोपनीय खेल अपना ढोल अलग बजाता है। सच दर्शक जानता है, क्योंकि वही खाली पड़े सिनेमाघर में मुट्ठी भर लोगों के बीच सौ-सौ करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म देख रहा होता है। मल्टीप्लेक्स, आइनॉक्स और दूसरे ऐसे ही मॉल केंद्रित सिनेमाघरों में फिल्म देखना फिल्म को देखने से ज्यादा अपने आसपास को देखने का अनुभव बन गया है। हॉल में प्रवेश करने से पहले, मध्यांतर का समय यह सब गैलरी की चमक-दमक को देखने, आपस में तौलने और मिलान करने की दृष्टि से ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है।

इधर 'नेटफ्लिक्स' या 'अमेजन प्राइम' आदि मानो सिनेमाघरों का स्पर्धी ही बन कर आ गए हैं। दिलचस्प यह है कि वही लोग जो अच्छी-बुरी फिल्म बनाते हुए खुद को अघाया हुआ महसूस कर रहे हैं, 'नेटफ्लिक्स' के लिए काम करने लगे हैं। इस माध्यम का अपना नेटवर्क फिलहाल बहुत प्रबल, संप्रेषणीय और असरदार भी है। यह सब देख कर लगता है कि अपने घर में ही बड़े स्क्रीन पर फिल्म देखने का अभ्यस्त दर्शक धीरे-धीरे सिनेमाघर का रास्ता भूल न जाए। हमारे ही सामने देखते-देखते सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर की संस्कृति समाप्त हो गई है। इसका श्रेय मल्टीप्लेक्स और आयनॉक्स जैसे माध्यमों को जाता है। अब इधर जिस तरह से 'नेटफ्लिक्स' या 'अमेजन प्राइम' जैसे नाम फन काढ़ कर सिनेमाघरों के सामने खड़े हो गए हैं। वह कहीं अवसर पाकर, आगे बढ़ कर इसे डस न ले, इस बात की चिंता होने लगी है।

जोखिम में जननी

समाज में माना जाता है कि सृष्टि की रचना स्त्रियों द्वारा ही होती है। एक स्त्री ही पुरुष की जननी होती है और वही पुरुष जब बड़ा हो जाता है तो उसी स्त्री के शरीर को नोचता, जलाता है। लगातार समाज में घट रहे अमानवीय कृत्यों ने स्त्रियों के जीवन को नरक बना दिया है। हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? जिस समाज में सृष्टि की जननी ही सुरक्षित नहीं है, वह समाज कैसा होगा? दशहरा में स्त्रियों को देवी मान कर पूजा की जाती है और फिर उन्हीं स्त्रियों पर अत्याचार की झड़ी लगा दी जाती है। उसी स्त्री को कभी दहेज के लिए जलाया जाता है तो कभी उसका बलात्कार किया जाता है तो कभी जन्म से पहले ही उसे भ्रूण में ही मार दिया जाता है। महिलाओं को कब तक इस पुरुष के समाज में घुट-घुट कर जीना पड़ेगा? कब तक दहेज के लिए वह जलती रहेगी? कब तक उनका बलात्कार होता रहेगा?

आखिर क्या गलती है स्त्री कि जो उनके साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। आज स्त्रियां कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नही कर पा रही हैं। ऐसे कितने मामले आ चुके हैं, जिसमें घर का ही कोई सदस्य या फिर कोई करीबी ही उनके खिलाफ यौन हिंसा करता है। स्त्रियां घर में हों या बाहर, कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। वे कौन लोग हैं हमारे समाज में जो दरिंदा बन कर समाज को कलंकित कर रहे हैं। अब हर इंसान को सोचना होगा कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित और दूसरे की बेटियों को चील की नजर से क्यों देखते हैं? अब वक्त आ गया है कि सरकार कोई बहुत बड़ा और ठोस कदम उठाए, जिससे स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति मिल सके और समाज को चाहिए कि अपने हर बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ाए, ताकि वह बलात्कार जिसे घिनौने करतूतों के खिलाफ खड़ा हो सके।

● *अनु मिश्रा, सिवान*

रोजगार की फिक्र

गत नवंबर माह में प्रधानमंत्री ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया गए थे। मौका था ब्रिक्स सम्मेलन। इस बैठक की थीम 'नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि' रखा गया था, क्योंकि विश्व के दो बड़े उपभोक्ता देश भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत की चिंता घरेलू मंदी है तो वहीं चीन अमेरिका के संरक्षणवादी नीति से परेशान है। भारत ने हाल ही में आरसीईपी में शामिल होने से मना कर दिया और कारण दिया कि शर्तों के अनुकूल न होने और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने आरसीईपी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है।

भारत के सभी कोर सेक्टर में मंदी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है इसका प्रमुख कारण बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वह खर्च कहां करे? इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार को इसके लिए त्वरित हल निकालना चाहिए।

● *संदीप कुमार ईसीसी, प्रयागराज*

ऊर्जा का खेल

अधिकतर विद्यालयों में हर वर्ष वार्षिकोत्सव के दौरान खेलकूद स्पर्धा का आयोजन होता है। स्कूलों और कॉलेजों की एक दिवसीय खेलकूद स्पर्धा के कारण खिलाड़ियों प्रदर्शन जड़वत दिखाई देता है तो आखिर उस स्पर्धा में कोई खिलाड़ी चैम्पियन कैसे बन जाए? दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, तिहरी कूद, चक्का फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो आदि खेलों को खेला जाता है। जो खिलाड़ी उस समय जीत जाता है, वह विजेता बन जाता है, लेकिन उसका वास्तविक खेल आधार जिला, संभाग, राज्य स्तर पर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता। खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षकों द्वारा खेलों के साथ स्टेमिना या ऊर्जा बढ़ाने जैसे उपाय किया जाना आवश्यक है। खिलाड़ियों में भी कुछ कर गुजरने जज्बा होगा तभी वे खेलों में आगे बढ़ सकते हैं। इन एथलीटों की तैयार पौध को स्टेमिना, खेल तकनीक अगर प्राप्त होगा तो वे आगे चल कर ओलिंपिक या एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर अपने गांव, शहर, देश का नाम रोशन करेंगे और साथ ही अन्य देशों की तरह खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा भी होगा। पदक संख्या बढ़ने से देश का नाम रोशन होगा।

● *संजय वर्मा 'दृष्टि', मनावर, धार*

स्त्री का भय

इतनी जल्दी तो शायद सरकार द्वारा चलाई गई युक्तिबद्ध नीतियां भी कार्यान्वित होनी आरंभ नहीं होती, जितनी जल्दी-जल्दी देश के लगभग हर कोने से बलात्कार और पीड़िता को मार डालने या जला देने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हैदराबाद में हुए निर्मम बलात्कार और हत्याकांड से शायद दूसरे अपराधी मर्दों ने सीख ली कि पहले स्त्री को मिल कर नोचो, फिर उसको जला दो, ताकि कोई सबूत न बचे। औरत चाहे बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में, पुरुष को क्या केवल उसमें अपनी वासना शांत करने का उपाय ही दिखता है? अगर ऐसा ही है, तो उसके आसपास की कोई भी स्त्री सुरक्षित नहीं हो सकती।

इसमें दो राय नहीं कि पुलिस, प्रशासन, कानून- सब इतने कड़े हो जाने चाहिए कि ऐसे अपराधियों को बेहद सख्त सजा मिले। 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड के बाद लगा जैसे इन हरकतों पर अब रोक लग गई है। लेकिन जल्दी ही यह सोच गलत साबित हुई। हैदराबाद, उन्नाव, कठुवा तो सुर्खियों में आ गई कुछ घटनाएं हैं, देश के हर छोटे-बड़े कोने से न केवल स्त्री का बलात्कार करने, बल्कि उसे जला देने की खबरों के आंकड़ों मे बढ़ोतरी दिखती है। कई बर्बरता को देख कर यही लगता है कि वे अपराधी ऐसा कर कैसे पाते हैं!

यह पुरुषों की आपराधिक मानसिकता नहीं तो क्या है कि अब उस मर्दवादी विचार की चपेट में आए कुछ किशोर भी बलात्कार की घटनाओं में हिस्सा लेने लगे हैं। ऐसे लड़के के पैदा होने पर क्यों खुशी मनाई जाती है, प्रलाप क्यों नहीं किया जाता। समाज, धर्म, नैतिकता का ठेकेदार कहे जाने वाला पुरुष खुद कितना खोखला है, इसका परिचय तो आए दिन मिलता रहता है। कभी-कभी मन सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या सच में हमारा देश विकास कर रहा है! इसका उत्तर बलात्कार मामलों मे आई वृद्धि दे रही है। एक तरफ हुंकार लगाई जाती है कि महिला आज तरक्की कर रही है। बेशक कर भी रही है, पर पुरुष समाज भी कभी उसका शारीरिक तो कभी मानसिक बलात्कार करने से बाज नहीं आता। आखिर क्यों वह स्त्री को हर कदम पर डर कर रहने को मजबूर कर ही देता है? क्यों वह यह एहसास दिलाता है कि जैसे स्त्री शरीर पाकर किसी लड़की ने कोई गलती कर गई हो!

● *अर्चना, रोहिणी पूर्व, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com